कांग्रेस का 'सर्जिकल-संकट'

लगता है कि पुलवामा हमले के फौरन बाद और आज की स्थिति में बदलाव है। हालात और बदलेंगे। सरकार पर हमले करते हुए भी उसे खुद को न तो पाकिस्तान-परस्त नजर आना है और न देश-विरोधी। वह कश्मीर के मामले में पाकिस्तानी नीतियों का समर्थन भी नहीं कर सकती। पार्टी ने मौके की नजाकत को देखते हुए पहले दौर में अपेक्षाकृत नरमी दिखाई थी, पर उसे यथार्थवादी राजनीति का रास्ता अपनाना होगा। कश्मीर में चल रहे पत्थर मार आंदोलन के संदर्भ में उसकी स्पष्ट रणनीति को सामने आना चाहिए। संयोग से अलगाववादियों ने यह रणनीति यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही अपनाई थी

■ प्रमोद जोशी
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पिछले बृहस्पतिवार को कहा कि पुलवामा आतंकी हमला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच 'मैच फिक्सिंग' का नतीजा है। हरिप्रसाद कांग्रेस के बहुत बड़े नहीं, तो छोटे नेता भी नहीं हैं। पिछले साल राज्य सभा के उप सभापति के चुनाव में पार्टी ने कर्नाटक के इस सांसद को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने बाद में सफाई दी कि हरिप्रसाद ने जो भी कहा है कि वह पार्टी का स्टैंड नहीं है, उनकी अपनी राय है। पर कैसी राय? उन्होंने मामूली बात नहीं कही है। साफ है कि पार्टी ने उनके बयान की अनदेखी की। यह अनदेखी सायास थी या अनायास?

पिछले महीने 14 फरवरी को पुलवामा कांड के फौरन बाद कांग्रेस ने सरकार को सहयोग का वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा था, हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं और हमें इस मामले में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। पर यह राहुल गांधी का बयान था। पार्टी की शुरुआती प्रतिक्रियाएं दो तरह की थीं। लगता था कि नेतृत्व इस मामले में सरकार पर हमले नहीं बोलेगा और अपनी छवि को एक जिम्मेदार राष्ट्रीय दल के रूप में बनाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने एक बयान भी जारी किया,...आतंकवादियों के हाथ शहीद हुए जवानों के परिवारों की वेदना मैं अच्छी तरह समझती हूं...शहीद परिवारों के पीछे न केवल कांग्रेस बल्कि पूरा देश खड़ा है। उन्होंने अपनी प्रस्तावित प्रेस कांफ्रेंस रद्द कर दी और कहा कि इस वक्त राजनीतिक सवालों पर चर्चा करना मुझे ठीक नहीं लगता।

जिम्मेदार पार्टी!

धर्मसंकट राहुल और प्रियंका के इन बयानों के विपरीत पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयानों में कुछ अंतर था। उनके ट्वीटों में कहा गया कि मोदी सरकार के रहते यह 18वां बड़ा आतंकी हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार का 56 इंची सीना इनका जवाब कब और कैसे देगा वगैरह? उन्होंने संवाददाताओं से कहा, आए दिन हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं। शहीद मनदीप और शहीद नरेन्द्र सिंह के सिर काटकर पाकिस्तानी ले गए, लेकिन मोदी जी चुप रहे। पांच हजार से अधिक बार सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, लेकिन मोदी जी चुप रहे। अब 44 जवान आतंकी हमले में शहीद हुए, मगर मोदी जी चुप हैं।

कांग्रेस पार्टी के सामने दो तरह के धर्मसंकट थे। एक; राष्ट्रीय संकट की बेला में उसे एक जिम्मेदार दल के रूप में खुद को पेश करना था, पर दूसरी तरफ यह बात साफ थी कि इस हमले से पैदा हुई हमदर्दी का पूरा लाभ बीजेपी लेने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के बयानों से कमोबेश यह बात जाहिर होने ही लगी थी। खासतौर से 26 फरवरी को बालाकोट पर हवाई हमले के बाद तो 'घर में घुसकर मारेंगे...' का इस्तेमाल मुहावरे की तरह होने लगा। कर्नाटक भाजपा के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इस हमले की बदौलत हम कर्नाटक की 28 में से 22 लोक सभा सीटें जीतने में सफल हो जाएंगे।

आरोपों की दुधारी तलवार

उसके अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने जम्मू-कश्मीर की वायुसीमा का उल्लंघन किया। हमारा एक मिग-21 विमान गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया। भारत सरकार की रणनीति के अंतर्विरोध भी सामने आने लगे। राजनीतिक बयानों की दिशा उसके बाद ज्यादा साफ होने लगी। सरकार की खामियां भी उजागर होने लगीं। बुधवार 27 फरवरी को जिस रोज कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों इस सिलसिले में बैठक की, तनाव अपने चरम पर था। इस बैठक में कांग्रेस की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी और उसके बाद जारी बयान दुधारी तलवार की तरह था। इसमें एक तरफ बालाकोट पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई और फिर पाकिस्तानी दुस्साहस को विफल करने की तारीफ की गई, वहीं यह भी आरोप लगाया गया कि पुलवामा हमले के बाद बीजेपी के नेताओं ने जवानों की शहादत का राजनीतिकरण किया जो चिंता का विषय है।

बैठक के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं के सामने विरोधी दलों का संयुक्त बयान पढ़ा था। इस बयान में कहा गया, 'राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थान राजनीतिक दलों की स्वार्थसिद्धि से कहीं ऊंचा होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।' हालांकि पुलवामा हमले के बाद राजनीतिक एकता को प्रदर्शित करने वाली एक सर्वदलीय बैठक हो चुकी थी, पर यह बैठक विरोधी दलों की एकता को प्रदर्शित करने वाली थी। इससे यह भी समझ में आता था कि लोक सभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनेगा, इसलिए उसकी पेशबंदी जरूरी है।

सामने खड़े सवाल

पुलवामा और बालाकोट प्रकरण के बरक्स आने वाले चुनाव के दौरान कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले विरोधी दलों की रणनीति से जुड़े दो-तीन सवाल महत्त्वपूर्ण बनेंगे, जो इस प्रकार हैं-

सितम्बर 2016 में कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी पर 'जवानों के खून की दलाली' का आरोप लगाया था। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ये लोग फर्जी राष्ट्रवादी हैं, जो सेना की बहादुरी पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। इस किस्म के बयानों का लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। इस बार पार्टी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो तारीफ की, पर बाद में सबूत भी मांगने शुरू कर दिए। क्या यह अंतर्विरोध नहीं है? कांग्रेस एक तरफ आतंकियों पर कार्रवाई न करने का तंज मारती है और दूसरी तरफ जब कार्रवाई होती है, तो उसमें छिद्र खोजती है।

बीजेपी सरकार का दावा है कि सन 1971 के बाद भारतीय वायुसेना ने पहली बार वायुसीमा के पार जाकर पाकिस्तान के सुदूर इलाके पर हमला किया है। सवाल यह नहीं है कि कितने मरे और कितने नहीं मरे। बात केवल इतनी है कि जैश के ट्रेनिंग सेंटर पर हमले राजनीतिक फैसला इस सरकार ने किया। ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? बीजेपी सरकार यह भी कहेगी कि हमारी कार्रवाई के कारण ही पाकिस्तान सरकार ने अपने जेहादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यह एक प्रकार की राजनीतिक बढ़त है। पुलवामा और बालाकोट के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बातचीत करने की पेशकश की है। इस बयान के कारण इमरान खान की तारीफ में बयान आए हैं। ऐसे बयानों में नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेताओं के नाम भी हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तारीफ में दिए गए बयान क्या कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? बीजेपी अब कांग्रेस पर पाकिस्तान के प्रति नरमी का रुख अपनाने का आरोप लगाएगी। गुजरात चुनाव के दौरान पार्टी ने ऐसा किया था।

मुद्दे बदलने की चुनौती

कांग्रेस के सामने आगामी लोक सभा चुनाव को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं। उसे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ऐसे ही दूसरे मुद्दों को भी शिद्दत से उठाना है, ताकि यह चुनाव पूरी तरह पुलवामा और बालाकोट तक सीमित न रह जाए। क्या वह जनता का ध्यान इनसे अलग कर पाएगी? ऐसा कैसे होगा? लगता है कि पुलवामा हमले के फौरन बाद और आज की स्थिति में बदलाव है। हालात और बदलेंगे। सरकार पर हमले करते हुए भी उसे खुद को न तो पाकिस्तान-परस्त नजर आना है और न देश-विरोधी। वह कश्मीर के मामले में पाकिस्तानी नीतियों का समर्थन भी नहीं कर सकती। पार्टी ने मौके की नजाकत को देखते हुए पहले दौर में अपेक्षाकृत नरमी दिखाई थी, पर उसे यथार्थवादी राजनीति का रास्ता अपनाना होगा। कश्मीर में चल रहे पत्थर मार आंदोलन के संदर्भ में उसकी स्पष्ट रणनीति को सामने आना चाहिए। संयोग से अलगाववादियों ने यह रणनीति यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही अपनाई थी।

सन 2014 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों में राष्ट्रवाद, मंदिर और पाकिस्तान के साथ रिश्ते कहीं थे ही नहीं। इसबार लगता है कि ये मसले चुनाव पर हावी रहेंगे। चुनाव के ठीक पहले पुलवामा कांड होने से बीजेपी को एक बनाबनाया मुद्दा मिल गया है। इन मुद्दों पर राय व्यक्त करने के साथ कई तरह के खतरे जुड़े हैं। खासतौर से शब्दों के फेर से पार्टी को बचना होगा। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा के साथ 'दुर्घटना' शब्द न जाने क्या सोचकर लगाया था, पर उसका असर कितना गहरा हुआ, यह बाद में पता लगा। ■

दाब में ऐसे लाया गया पाकिस्तान

■ अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

भारत के गैरजिम्मेवार और नासमझ नेता भले पाकिस्तान विरोधी कार्रवाई का उपहास उड़ा रहे हों लेकिन इसका गहरा असर पाकिस्तान एवं दुनिया पर हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तेजी से भारत द्वारा चिह्नित संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वे इस बात के प्रमाण हैं कि यह सब वायु सेना की कार्रवाई तथा कूटनीतिक दबाव में किया गया है। पंजाब प्रांत सरकार ने 7 मार्च को प्रतिबंधित संगठन जमात-उद्-दावा (जेयूडी) और फलाह-ए-इंसानियत (एफआईएफ) के मुख्यालय के साथ लाहौर एवं अन्य स्थानों पर स्थित जेयूडी की मस्जिदों, मदरसों, डिस्पेंसरियों को अपने अधिकार में ले लिया। यह सामान्य कदम नहीं है। भारत के लोगों ने इन संगठनों के संचालक और भारत के लिए आतंकवाद के दो प्रमुख दुश्मनों में से एक हाफिज सईद का ऐसा दयनीय चेहरा पहली बार देखा और थरथराती आवाज भी पहली बार सुनी। 5 मार्च को पाकिस्तान ने जमात-उद्-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित सूची में डाला था, जिसके बाद इनकी संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रकिया आरंभ हुई। इसके साथ, जैश-ए-मोहम्मद के 44 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया जिनमें मसूद अजहर का भाई और बेटा शामिल हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (एनएसीटीए) की सूची को पाकिस्तान ने संशोधित किया है। इसके अनुसार अनुसार जमात और एफआईएफ आतंकवाद निरोधक कानून, 1997 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 70 संगठनों में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) बनी हुई है। किंतु इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। 4 मार्च तक एनसीटीए की वेबसाइट पर इन संगठनों को निगरानी संगठनों की सूची में ही रखा गया था। तो यह बदलाव हवाई बमबारी के बाद हुआ। जाहिर है, यह बदलाव पाकिस्तान की मजबूरी है।

जाहिर है, पाकिस्तान को आगे इस तरह की और कार्रवाइयां करनी होंगी। जैश के 44 लोगों को हिरासत में लेना भी बड़ी खबर है। हालांकि इसके बारे में हमारे पास उतनी ही सूचना है, जितनी पाकिस्तान के गृह मंत्री शहरयार खान आफरीदी ने पत्रकारों को दी। आफरीदी का बयान है कि छापामारी के दौरान हिरासत में लिए गए जैश के 44 सदस्यों में अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुर रऊफ और बेटा हम्माद अजहर भी शामिल हैं। आफरीदी कहना नहीं भूले कि भारत ने जो डोजियर सौंपा है, उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। यह भारत के साथ दुनिया को संदेश देने की कोशिश है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहे। तो क्या मान लिया जाए कि वाकई पाकिस्तान अब रास्ते पर आ गया है, और भारत केंद्रित आतंकवाद के संसाधनिक, वैचारिक एवं मानवीय स्रोतों को ध्वस्त करने लगा है? यह बात सही है कि 5 मार्च को पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जिसमें देश की सभी प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

पाकिस्तान पर भारी दबाव

पाकिस्तान इस समय अब तक के सबसे भारी दबाव में है। भारत की हवाई बमबारी के बाद उसके सामने साफ हो गया है कि अगर हमने इनके भवनों को नियंत्रण में नहीं लिया तो आगे भी ऐसा होगा। भारत उन सारे आतंकी संगठनों के भवनों तथा प्रमुख आतंकवादी चेहरों को निशाना बनाएगा। भारत ने साफ शब्दों कहा है कि आगे आतंकी हमला हुआ तो वह कार्रवाई करेगा। आतंकी संगठनों के अंदर तो भय पैदा हो ही गया है कि भारत उनको कहीं भी निशाना बना सकता है, पाकिस्तान भी इसी मनोदशा से गुजर रहा है। इमरान खान और उनके अन्य मंत्री बड़बोलापन चाहे जितना दिखाएं पर उन्हें पता है कि भारत ऐसा करेगा तो उन्हें अवाम की नजर में अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ जवाबी कार्रवाई करनी ही होगी। उसमें उसे किसी का साथ नहीं मिलेगा। फिर युद्ध का परिणाम उसके लिए ज्यादा विनाशक होगा। पाकिस्तान के अंदर यह भय पैदा होना भारतीय कार्रवाई की ऐतिहासिक सफलता है। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान का पूरा मनोविज्ञान बदल गया है।

भारत ने एक परिपक्व और मजबूत देश का परिचय देते हुए संदेश दिया है कि हमारे यहां सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, और आगे भी कार्रवाई से हम पर कोई अंतर नहीं आएगा। इसके साथ भारत ने कूटनीतिक गतिविधियां तेज की हैं। वीटो पावर वाले तीन देश, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पेश किया है। परिषद के 15 में से 14 सदस्य राष्ट्र मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने को तैयार हैं। वीटो शक्ति के कारण चीन तीन बार इस प्रस्ताव को गिरा चुका है। फ्रांस, ब्रिटेन एवं अमेरिका ने कहा है कि चीन वीटो करता है तो वे भी वीटो करेंगे। एक के समानांतर तीन वीटो आने पर यह पारित हो जाएगा। पाकिस्तान को इसका आभास है। भारतीय कूटनीति का त्वरित परिणाम पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को आतंक के वित्त पोषण पर रोक लगाने की चेतावनी के रूप में सामने आया। इस संस्था ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। टास्क फोर्स के अनुसार, अक्टूबर, 2019 तक यदि पाकिस्तान उसकी 27 मांगों पर काम नहीं करता है, तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा यानी काली सूची में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कई बयानों में स्वीकार किया है कि भारत उसे काली सूची में डलवाने के लिए काम कर रहा है, जिससे हमें बचना है। भारत अनेक देशों के प्रमुखों और दूतावासों से संवाद कर उनको या तो अपने पक्ष में लाया है, या फिर ऐसी स्थिति बनाई है कि वह किसी तरह विरोध में न जाएं।

इस्लामी सम्मेलन संगठन या ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों, जो पाकिस्तान के मजहबी भाई माने जाते रहे हैं, में से भी किसी ने भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन करने की आलोचना तक नहीं की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दौरा कर चीनी नेताओं के सामने अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान की वायु सेना का एफ 16 लेकर नियंत्रण रेखा पार करना भी उसके लिए महंगा पड़ गया है। उसने एफ 16 के प्रयोग से इनकार किया जबकि भारत ने सबूत के साथ इसे साबित कर दिया। अब अमेरिका एफ 16 के उपयोग को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

पाकिस्तान की मनोदशा

प्रधानमंत्री इमरान खान का संसद में दिया गया बयान तथा देश को संबोधन में शांति एवं मेल-मिलाप की भाषा थी। 5 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने योजनापूर्वक जिओ टीवी को एक साक्षात्कार दिया। उसमें कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपने हितों को लेकर फैसला करना ही होगा। हमारी कुछ वैश्विक प्रतिबद्धताएं हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस समय अपने देश को बचाने के लिए सारी कार्रवाइयां कर रहा है। ध्यान दीजिए आफरीदी ने भी यही कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई देश के हित के लिए है। देशहित शब्द में पाकिस्तान की पूरी स्थिति एवं मनोदशा निहित है। किंतु इससे भारत को उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने कहा भी है कि 44 आतंकवादियों को हिरासत में लेना दरअसल, उनको सुरक्षा में ले आना है। आफरीदी के पूरे बयान में इनको आतंकवादी मान लेने या सजा दिलाने को कोई प्रतिबद्धता नहीं है। उनका बयान है कि हिरासत में लिए गए कथित आतंकवादियों की खिलाफ उपलब्ध सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर कार्रवाई का मतलब क्या है? सबूत क्या? जो भारत ने डोजियर में दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने 6 मार्च को कहा कि भारत ने एक डोजियर भेजा है, जिसे हम देख रहे हैं। अगर इसमें कुछ ठोस मिलता है, तो ही हम कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? सबूत तो आपके यहां हैं। जैश ने पुलवामा हमले की जिम्मेवारी ली, इसके पहले पठानकोट और उरी उसने अंजाम दिया, संसद हमले में जैश एवं लश्कर शामिल थे, मुंबई हमला लश्कर की कार्रवाई थी। तो सबूत एकत्रित करना आपका काम है।

कहने का तात्पर्य यह कि पाकिस्तान फिर न्यायालय में ठहरने योग्य सबूत न होने की आड़ लेगा। जैश के आतंकवादियों को भी आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया है। ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान ने पहले भी की है, जिसका परिणाम उनके आराम से बाहर आकर आतंकवादी गतिविधियां जारी रखने के रूप में ही आया। तो ये सब आगे आराम से रिहा कर दिए जा सकते हैं। जिस तरह उसने निगरानी सूची से निकाल कर संगठनों को प्रतिबंधित सूची में डाला वह भी शायद किसी बहाने आगे खत्म कर दिया जाए। भारत की कूटनीति उस पर केंद्रित है, और सारे देशों को पाकिस्तान के एक-एक चाल से अवगत कराया जाएगा। लेकिन इस समय बदला हुआ भारत है। पाकिस्तान क्या करता है, इससे अब भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वला। भारत का निर्णय साफ है, हम स्वयं सीमा पार करके हमले की जड़ों को मिटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक भाषण में कहा कि वो पाताल में छिपे होंगे तो वहां भी हम मारेंगे। यह भी कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे। ये बयान पाकिस्तानी मीडिया में खूब चल रहे हैं। पाकिस्तान इसको ध्यान में रखकर अपनी कार्रवाई करे, यही उसके हित में होगा। ■

प्रधानमंत्री इमरान खान का संसद में दिया गया बयान तथा देश को संबोधन में शांति एवं मेल-मिलाप की भाषा थी। 5 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने योजनापूर्वक जिओ टीवी को एक साक्षात्कार दिया। उसमें कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपने हितों को लेकर फैसला करना ही होगा। हमारी कुछ वैश्विक प्रतिबद्धताएं हैं

बयान नीति

एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ- *वायु सेना लाशें गिनने का काम नहीं करती। अगर हम जंगल में बम गिराते तो पाकिस्तान जवाबी हमला क्यों करता?*

निर्मला सीतारमण- *भारतीय विदेश सचिव ने इस मुद्दे पर पहले ही बयान दिया है और वही भारत सरकार का आधिकारिक बयान है।*

नरेन्द्र मोदी- *मैं ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करता, चुन-चुनकर हिसाब लेना मेरी फितरत है। भारत में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार लोग अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो वह उन्हें खोज निकालेंगे। 40 साल से आतंकवाद हिन्दुस्तान के सीने में गोलियां दाग रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोग कदम उठने से डरते थे। भारत में विपक्ष के नेता जो बयानबाजी करते हैं, वे पाकिस्तान के अखबारों की हेडलाइंस बन जाती हैं। क्या यह बात देशहित के लिए सही है?*

नीतीश कुमार- *यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बात देश की एकता और अखंडता की है। इस पर पूरे देश में सब लोगों की भावना एक है। इस पर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए।*

ममता बनर्जी- *मोदी-बाबू, हमले (पुलवामा हमला) के समय आप कहां थे? आपको पहले से पता था कि यह घटना होगी। आपके पास पहले से जानकारी थी। केंद्र सरकार के पास इस संबंध में खुफिया जानकारी थी। फिर जवानों को उस दिन हवाई मार्ग से क्यों नहीं जाने दिया गया? काफिले के मार्ग की नाका जांच क्यों नहीं की गई? जवानों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए कि आप चुनावों से पहले मामले का राजनीतिकरण करना चाहते थे। हमारे जवानों के खून का इस तरह राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मोदी शांति के संदेशवाहक होने का नाटक करते हैं। वहीं उनकी पार्टी गुप्त रूप से देश में युद्ध समान परिस्थितियां पैदा करना चाहती है और दंगा शुरू कर देती है।*

अरविंद केजरीवाल- *देश शहीदों के गम में रो रहा था. देश गुस्से में था, अपमानित महसूस कर रहा था। मंगलवार को देश ने सख्त संदेश पाकिस्तान को दिया, पर दोबारा देश की आत्मा रो पड़ी। जब देश और जवान नहीं बचेगा तो वूथ कहां से बचेगा। आखिर, चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी को कितनी लाशें चाहिए।*

पी. चिदंबरम- *भारतीय वायु सेना के वाइस एयर मार्शल ने हताहतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कोई नागरिक या सैनिक हताहत नहीं हुआ। तो, हताहतों की संख्या 300-350 किसने बताई? एक नागरिक के तौर पर मैं अपनी सरकार पर भरोसा करने के लिए तैयार हूं. लेकिन, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया को भी भरोसा हो तो सरकार को विपक्ष को कोसने की बजाय इसके लिए प्रयास करना चाहिए।*

कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह- *पुलवामा के बाद राहुल गांधी ने सेना और सरकार के साथ खड़े होने की बात की। हम अपनी सेना और वायु सेना के साथ खड़े हैं। पीएम का आरोप झूठ कि हम सेना पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिकरण तो भाजपा अध्यक्ष ने किया है।*

वीके सिंह- *एक आतंकी हमले को 'दुर्घटना' करार देना, हमारे देश में राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? दिग्विजय सिंह जी, क्या आप राजीव गांधी की राजनीतिक हत्या को एक 'दुर्घटना' करार देंगे? इन फालतू के बयानों से देश को कमजोर न बनाएं और सैन्य बलों का मनोबल कम न करें।*

रविशंकर प्रसाद- *ये लोग सेना से सबूत मांग रहे हैं, और इन्हें सेना पर भरोसा नहीं है। ये जवानों की शहादत का मजाक बना रहे हैं।*

दिग्विजय सिंह- *हमें हमारी सेना पर और उनकी बहादुरी पर गर्व है व संपूर्ण विश्वास है। किंतु पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायु सेना द्वारा की गई 'एयर स्ट्राइक' के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिह्न लग रहा है।*

कपिल सिब्बल- *मोदी जी! क्या, इंटरनेशनल मीडिया...न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, द गार्जियन, रॉयटर्स ने बालाकोट में आतंकियों को किसी तरह का नुकसान न होने का सुबूत दिया है? आप, आतंक का राजनीतिकरण करने के लिए दोषी हैं?*

राज्यवर्धन सिंह राठौर- *क्या आप, खुद की इंटेलीजेंस एजेंसियों से कहीं ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर भरोसा करते हैं? आपको खुशी होती है जब मीडिया स्ट्राइक में किसी तरह का नुकसान न होने की बात कहता है...और सर, हमारे लिए आप ईवीएम के खिलाफ सुबूत खोजने लंदन गए थे, क्या आप बालाकोट भी जांच के लिए जाएंगे।*

बसपा सुप्रीमो मायावती- *भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दावा करते हैं कि एयर फोर्स की स्ट्राइक में 250 आतंकवादी मारे गए हैं लेकिन उनके गुरु जो हमेशा हर बात पर क्रेडिट लेते हैं, इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।*

हरदीप सिंह पुरी- *पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने से मुंह चुराया। मौजूदा नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस सिलसिले को बदला है।*

नवजोत सिंह सिद्धू- *वहां आतंकियों को मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने। क्या मुट्ठी भर लोगों के लिए एक पूरे देश को या किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, न आतंकियों का कोई मजहब।*

बीके हरिप्रसाद- *पुलवामा हमले के बाद के घटनाक्रम पर यदि आप नजर डालेंगे तो पता चलता है कि यह पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग थी।*

भाजपा नेता दिलीप घोष- *भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं, इसके लिए ममता बनर्जी ही काफी हैं। ममता बनर्जी ने बालाकोट हवाई हमले में हताहतों की संख्या पर शक जताया है और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान देश के हितों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इस काम को करने में सक्षम है।*

हरियाणा के मंत्री अनिल विज- *अगली बार भारत जब पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों पर बम गिराएं तो महागठबंधन के किसी नेता को नीचे खड़ा कर देना चाहिए ताकि वह लाशें खुद गिन सके।*